



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2014/ज्येष्ठ 27, 1936

No. 182]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2014/JYAISTHA 27, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 जून, 2014

सं. टीएमपी/28/2014-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, राजपत्र सं. 254 द्वारा अधिसूचना सं. टीएमपी/18/2013-विधि दिनांक 30 सितम्बर 2013 द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों' में पत्तन परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013' के अधीन बीओटी आधार पर पारादीप पत्तन में लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन के लिए विकसित किए जाने वाले नए लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएमपी/28/2014- पीपीटी)

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i) श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जून 2014 के 5वें दिन पारित)

यह मामला महापत्तनों में पत्तन परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 के अधीन, बीओटी आधार पर पारादीप पत्तन में लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन के लिए विकसित किए जाने वाले नए लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. इस प्राधिकरण ने महापत्तनों में पीपीटी परियोजनाओं के लिए अप्रकट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008 के अनुसरण में, पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में विकसित किए जाने वाले गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क बर्थ और गहरे डुबाव वाले कोयला बर्थ के लिए अप्रकट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए आदेश सं. टीएमपी/18/2008-पीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 पारित किया था। यह आदेश 16 अगस्त 2008 को राजपत्र सं. 133 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.1. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा 31 जुलाई 2013 को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन 'महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013' जारी किए थे। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन (एमओएस) द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में, उक्त दिशानिर्देश 8 अगस्त 2013 को राजपत्र सं. 214 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. टीएमपी/18/2013-विधिविध द्वारा अधिसूचित किए गए थे। उक्त दिशानिर्देश 31 जुलाई 2013 से लागू हुए थे।

2.2. तत्पश्चात्, एमओएस ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013 जारी किए थे और 9 सितम्बर 2013 से लागू किए गए थे। उक्त संशोधित दिशानिर्देश 30 सितम्बर 2013 को राजपत्र सं. 254 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे।

3.1. महापत्तनों में पत्तन परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 के अनुसरण में और अगस्त, 2013 में पीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/37/2013-पीपीटी दिनांक 30 अगस्त 2013 द्वारा पीपीटी में बीओटी आधार पर विकसित की जाने वाली 10 एमएमटीपीए क्षमता के गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किया है। यह आदेश 20 सितम्बर 2013 को राजपत्र सं. 245 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3.2. यह उल्लेखनीय है कि अगस्त 2013 में ऐसा निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क देय वृद्धि कारक लागू करने के बाद (उपर्युक्त प्रारंभिक पैरा में यथा उल्लिखित) वर्ष 2008 में अनुमोदित पीपीटी पर लौह अयस्क परियोजना की अप्रकट प्रशुल्क दरों पर आधारित था।

3.3. तत्पश्चात्, इस प्राधिकरण ने पीपीटी आदेश में 2013 के दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट कुछ प्रासंगिक खंड निर्धारित करने के लिए आदेश दिनांक 30 अगस्त 2013 में एक अनुशेष दिनांक 5 दिसम्बर 2013 भी पारित किया था। यह अनुशेष 26 दिसम्बर 2013 को राजपत्र सं. 333 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

4. इस परिप्रेक्ष्य में, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 मई 2014 के कवर के तहत महापत्तनों में पत्तन परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 के अधीन बीओटी आधार पर पारादीप पत्तन में लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन हेतु विकसित किए जाने वाले नए लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल किया था। पीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- (i) 'पारादीप पत्तन में बीओटी आधार पर गहरा डुबाव लौह अयस्क बर्थ' के लिए अप्रकट प्रशुल्क हेतु अधिसूचना 16 अगस्त 2008 को जारी की गई थी।
- (ii) ये प्रशुल्क मामला सं. टीएमपी/37/2013-पीपीटी दिनांक 30 अगस्त 2013 द्वारा सूचकांकित किए गए थे और परियोजना दोबारा टेंडर के लिए रखी गई थी।
- (iii) तथापि, इसने अब वर्तमान टेंडर के निवर्तन का निर्णय लिया है और आरएफक्यू स्टेज से दोबारा बोलियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए आरएफक्यू मई 2014 में जारी किया जाएगा। चूंकि परियोजना के लिए आरएफपी दस्तावेजों में विभिन्न सेवाओं के लिए 2014 के लिए सूचकांकित परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क शामिल होना चाहिए, इसलिए प्रशुल्क प्रस्ताव 30 सितम्बर 2013 को अधिसूचित 'महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013' के आधार पर तैयार किया गया है।
- (iv) प्रशुल्क 2008 के अनुमोदित प्रशुल्क (2013 के अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर 4.3 प्रतिशत) के आधार पर 31.58 प्रतिशत तक सूचकांकित किए गए हैं।

4.2. पीपीटी ने अपने प्रस्ताव के साथ लौह अयस्क टर्मिनल के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची और कार्यनिष्पादन मानक' भेजे हैं।

5. एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित बिन्दु विचारार्थ प्रकट होते हैं:-

- (i) जुलाई 2008 में पीपीटी में लौह अयस्क बर्थ के लिए निर्धारित अप्रकट प्रशुल्क के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अगस्त 2013 के अपने आदेश द्वारा पीपीटी में लौह अयस्क सुविधा के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किया था। ऐसा निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क (1 जनवरी 2008 को आधार डब्ल्यूपीआई के साथ प्रशुल्क हेतु लागू किए जाने वाले वर्ष 2013 हेतु लागू सूचकांकन कारक होते हुए) 26.15 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू करने के बाद था।
- (ii) इस आधार पर कि पीपीटी ने अपना टेंडर डिस्चार्ज करने और बोलियां दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय लिया है और कि चूंकि परियोजना के लिए आरएफपी दस्तावेज में विभिन्न सेवाओं के लिए 2014 हेतु सूचकांकित परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क होना चाहिए, इसलिए पीपीटी ने संदर्भित प्रस्ताव जमा किया है।
- (iii) 2013 दिशानिर्देशों का खंड 2.8 विनिर्दिष्ट करता है कि पीपीटी परियोजनाओं के अवार्ड के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी और उस समय प्रचलित संदर्भ प्रशुल्क के आधार पर मूल्यांकित की जाएंगी। चूंकि पीपीटी ने वर्ष 2014 के दौरान बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए वर्ष 2014 के लिए यथा लागू संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित करने की जरूरत दिखाई देती है।
- (iv) 2013 के संशोधित दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि संदर्भ प्रशुल्क अंगीकृत करते समय, 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित प्रशुल्क में प्रतिवर्ष डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि की जाएगी, जैसाकि 2008 दिशानिर्देशों के अधीन इस प्राधिकरण के प्रासंगिक प्रशुल्क आदेश में यथा निर्धारित वर्ष के 1 जनवरी और अनुवर्ती प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी, जब प्रश्नाधीन परियोजना विशेष के लिए संदर्भ प्रशुल्क अधिसूचित किया जाना है, के बीच की अवधि के लिए उक्त दिशानिर्देशों में दिया गया था।
- (v) जैसाकि पहले बताया गया है, पीपीटी लौह अयस्क बर्थ के लिए अप्रकट प्रशुल्क जुलाई 2008 में अधिसूचित किया गया था। पीपीटी की अप्रकट प्रशुल्क अनुसूची में विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क दरों में सूचकांकन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का आधार वर्ष 1 जनवरी 2008 होगा। तदनुसार, पीपीटी ने जुलाई 2008 के आदेश द्वारा पीपीटी लौह अयस्क बर्थ के लिए अनुमोदित प्रशुल्क सीमाओं पर 31.58 प्रतिशत का सूचकांकन कारक लागू किया है। यह सूचकांकन कारक 1 जनवरी 2008 को आधार

डब्ल्यूपीआई के साथ वर्ष 2014 में निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क के लिए लागू किए जाने वाले सभी महापत्तन न्यासों को हमारे द्वारा संप्रेषित सूचकांकन कारक देखा गया है। वर्ष 2014 के लिए यथा लागू 31.58 प्रतिशत के सूचकांकन कारक के आधार पर पीपीटी द्वारा यथा विपथित लौह अयस्क बर्ध के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क सही पाया गया है।

- (vi) प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में, पीपीटी ने पीपीटी संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची के हिस्से शर्तें और सामान्य निबंधन एवं शर्तें प्रस्तावित नहीं की हैं। इसके अलावा, कार्गो प्रहस्तन प्रभारों, भंडारण प्रभारों और बर्ध किराया प्रभारों की वसूली को शासित करने वाली विभिन्न शर्तें भी पीपीटी द्वारा प्रस्तावित की गई नहीं देखी गई हैं। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जुलाई 2008 में अनुमोदित पीपीटी में लौह अयस्क बर्ध के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में कार्गो प्रहस्तन प्रभारों, भंडारण प्रभारों और बर्ध किराया प्रभारों, जोकि सामान्य तौर पर विभिन्न महापत्तन न्यासों की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित की जाती है, की वसूली को शासित करने वाली परिभाषाएं, सामान्य निबंधन एवं शर्तें और विभिन्न शर्तें निर्धारित नहीं की गई थीं। इसलिए, मुरुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) (आदेश सं. टीएमपी/60/2009—एमओपीटी दिनांक 4 मई 2010) में लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची के हिस्से कार्गो प्रहस्तन प्रभारों, भंडारण प्रभारों और बर्ध किराया प्रभारों की वसूली को शासित करने वाली परिभाषाएं, सामान्य निबंधन एवं शर्तें और सभी अन्य शर्तें पीपीटी के संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में उपयुक्ततः निर्धारित किए गए हैं।
- (vii) 2013 के संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.2 इस प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि कार्यनिष्पादन मानकों के साथ संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किया जाए। पीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों को शासित करने वाली शर्तें और कार्यनिष्पादन मानक आदेश दिनांक 30 अगस्त 2013 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित के समान पाए गए हैं। अतः, पीपीटी द्वारा अब प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक और शर्तें बिना किसी संशोधन के अधिसूचित किए गए हैं।
- (viii) भविष्य अवधि के लिए संदर्भ प्रशुल्क के सूचकांकन को शासित के लिए पीपीटी द्वारा प्रस्तावित टिप्पणी 1 जनवरी 2013 संदर्भ में है। चूंकि संदर्भ प्रशुल्क, पीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित, 31 दिसम्बर 2013 को विधिवत् यथा अद्यतन किए वर्ष 2014 में निर्धारित किया गया है, इसलिए भविष्य अवधि के लिए सूचकांकन 1 जनवरी 2014 संदर्भ में होगा। इसलिए, निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी प्रत्येक अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रशुल्क सीमाओं में स्वतः समायोजन के लिए पीपीटी की संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित की गई है:

“प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु 1 जनवरी 2014 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।”

6.1. उपर्युक्त के अधीन, पत्तन द्वारा प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची संशोधित की गई है। संशोधित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची **अनुबंध-I** और पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित लौह अयस्क बर्ध के लिए कार्यनिष्पादन मानक **अनुबंध-II** रूप में संलग्न किए गए हैं।

6.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, पीपीटी में लौह अयस्क बर्ध के लिए संशोधित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची अनुमोदित की गई है और कार्यनिष्पादन मानकों के साथ अधिसूचित किया गया है।

6.3. संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खंड 2.5 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक बोली दस्तावेज में उल्लिखित किए जाएंगे और बाद में पीपीटी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में उल्लिखित किए जाएंगे। तदनुसार, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि पीपीटी परियोजनाओं के मामले में संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक बोली दस्तावेज में और बाद में रियायत करार में शामिल किए जाएं।

7.1. वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क उस वर्ष के प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा जोकि अधिकतम होगा। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यथा उपलब्ध सूचकांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः संशोधित किया जाएगा जोकि सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए लागू होगा।

तथापि, पीपीटी प्रचालन अनुगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से अधिक प्रचालन के दूसरे वर्ष से कार्यनिष्पादन मानकों (“कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रशुल्क”) के साथ प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क सीमा होगी)। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अगले वित्तीय वर्ष के अगले दिन से लागू होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगी।

7.2. यह प्रस्ताव रियायत करार में यथा शामिल पिछले 12 महीनों में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए अथवा प्रचालन के प्रथम वर्ष में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या के लिए, जैसी भी स्थिति हो, परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर से प्रमाणपत्र के साथ इस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.3. प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यह प्राधिकरण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में दिए गए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर पीपीटी के विचार प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर मांग करेगा।

7.4. पिछले 12 महीनों में रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानकों को प्रचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, यह प्राधिकरण अनुगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और प्रचालक अनुगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू केवल सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के लिए हकदार होगा।

7.5. पीपीटी के मतों पर विचार करने के बाद, यदि यह प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानक अर्जित किए गए हैं, तो यह अनुगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क मार्च के 15वें दिन तक अधिसूचित करेगा।

7.6. कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण कार्यनिष्पादन मानकों को देखेगा और प्रचालक द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा। यह प्राधिकरण प्रचालक द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा पर आधारित कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क स्वीकार करने अथवा खारिज

करने पर निर्णय लेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों से जुड़े परिशिष्ट में निर्दिष्ट उदाहरण का अनुसरण करेगा।

7.7. प्रचालन के तीसरे वर्ष से, पीपीटी प्रचालक से कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित पिछली 12 महीनों की अवधि में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा स्वतः अधिसूचित किया जाएगा। पीपीटी प्रचालक, तीसरे वर्ष से कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए, स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाणपत्र के साथ कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव 1 मार्च तक प्रस्तुत करेगा और यह प्राधिकरण अनुगामी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाने वाला कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा।

7.8. यदि किसी उपयोक्ता को इस प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों के पीपीटी प्रचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत होती है तो वह इस प्राधिकरण को अभ्यावेदन दे सकता है जो, उसे बाद, अभ्यावेदन की जांच करेगा और अपने निष्कर्ष पीपीटी को देगा। पीपीटी तत्संबंधी रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार निष्कर्ष पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

7.9. रियायत करार पर हस्ताक्षर होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, संबद्ध प्रचालक रियायत करार इस प्राधिकरण को भेजेगा जो उसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

7.10. पीपीटी प्रचालक कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों की वापसी का औसत समय, औसत प्रि-बर्थिंग प्रतीक्षा समय एवं प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किया गया प्रशुल्क पर तिमाही रिपोर्ट इस प्राधिकरण को भेजेगा। तिमाही रिपोर्टें प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के भीतर पीपीटी प्रचालक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। कोई अन्य सूचना जो इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित की जाती है, भी उन्हें समय-समय पर भेजी जाएगी।

7.11. यह प्राधिकरण पीपीटी प्रचालक से सभी ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तथापि, यह प्राधिकरण वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील प्रेषित कुछ आंकड़ों/सूचना प्रकाशित नहीं करने के बारे में किसी पीपीटी प्रचालक से अनुरोध पर विचार करेगा। ऐसे अनुरोधों के साथ प्रश्नाधीन आंकड़ों/सूचना की वाणिज्यिक संवेदनशीलता और प्रकाशन होने पर उनके राजस्व/प्रचालन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में विस्तृत औचित्य दिए जाने चाहिए। इस संबंध में इस प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/2014]

अनुबंध — I

पारादीप पत्तन में बीओटी आधार पर लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन के लिए विकसित किए जाने वाले नए

लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची

1.1. परिभाषाएँ – सामान्य

इस दरमान में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

- (i) "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii) "विदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii) "प्रतिदिन" का अर्थ प्रति केलेंडर दिवस होगा जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया जाए।

1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

- (i) पोत संबंधित प्रभारों की वसूली करने के प्रयोजन के लिए "तटीय" अथवा "विदेशगामी" पोत के रूप में इसका वर्गीकरण करने के लिए सीमाशुल्क अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र पोत का दर्जा निर्णायक कारक होगा; और, इस प्रयोजनार्थ कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उद्गम का इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।
- (ii) (क) सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ख) ताप कोयले से इतर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ग) कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान-तट स्थानांतरण और घाटशुल्क सहित घाट से भंडारण यार्ड/भंडारण यार्ड से घाट के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जानी चाहिए।
(घ) विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन 'ख' को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, से उसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे। अन्य शब्दों में, तटीय नौचालन के लिए अनुमत पोत द्वारा भारतीय पत्तनों से/को कार्गो ढोना रियायत के लिए पात्र होगा।
- (iii) विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:
(क) उपयोक्ता को इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा। इसी तरह, टर्मिनल प्रचालक को विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा।
(ख) दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधार उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।
(ग) वापसियों पर विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख के 20 दिन बाद से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, परिगणित किया जाएगा।

- (घ) उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिलों को दिए जाने की तारीख के 10 दिन बाद से परिगणित किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाता है जहां प्रभारों का अग्रिम भुगतान दरमान में एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- (iv) सभी परिगणित प्रभार प्रत्येक बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (v) (क) इस दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट प्रदान कर सकता है।
- (ख) टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन पर शासित निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत भी बना सकता है यदि युक्तिकरण से उपयोक्ताओं को दर प्रति इकाई में राहत मिलती है और दरमान में निर्धारित इकाई दरें अधिकतम स्तर से अधिक नहीं हों।
- (ग) परन्तु टर्मिनल प्रचालक को ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन पर शासित शर्तों के युक्तिकरण के बारे में सार्वजनिक अधिसूचना देनी होगी और ऐसी दरों के लागू करने को शासित करने वाली शर्त में और/अथवा ऐसी निम्नतर दरों में किसी और बदलाव को अधिसूचित करना जारी रखना होगा, परन्तु नई निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (vi) उपयोक्ताओं को प्रचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंबों के लिए प्रभारों की अदायगी नहीं करनी होगी।

2. कार्गो संबंधित प्रभार:

पारादीप पत्तन न्यास में लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन के लिए नए लौह अयस्क बर्थ पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर कार्गो के आयातक द्वारा सीधे विनिहित कार्गो पर देय होगा:

क्र.सं.	घटक	इकाई	दर रु. में
1.	लौह अयस्क प्रहस्तन प्रभार (सभी प्रकार)	मी.ट.	206.58

टिप्पणी :

उपर्युक्त दर रेलवे वैगन से लौह अयस्क की उतराई, स्टैक यार्ड में ले जाने, रेलवे वैगन से लौह अयस्क की उतराई के समय के 18 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टैकयार्ड में भंडारण, स्टैक यार्ड से रिक्लेमिंग और जलयान पर लदाई तथा सभी अन्य विविध सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

3. भंडारण प्रभार:

निःशुल्क अवधि के बाद स्टैकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होगा:

(रु0 प्रति मी.ट. प्रतिदिन)

क्र. सं.	घटक	निःशुल्क अवधि के बाद रहने वाले शेष कार्गो के लिए प्रथम 5 दिनों हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10वें दिन के लिए दर	शेष कार्गो के लिए 11वें दिन से आगे के लिए दर
1.	लौह अयस्क गुट्टिकाएं (सभी प्रकार)	15.79	31.58	63.16

टिप्पणियां :

- (i) निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त होंगे।
- (ii) आयात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि पोत से फाइनल उतराई के पूरा होने के दिन के अगले दिन से गिनती की जाएगी।
- (iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होगा जब टर्मिनल प्रचालक टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य कारणों की वजह से तब कार्गो की डिलीवरी/नौभरण की स्थिति में नहीं हो जब उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है।

4. बर्थ किराया प्रभार:

पोत के लिए मास्टर्स/मालिकों/एजेंटों द्वारा देय बर्थ किराया प्रभार निम्नलिखित दरों के अनुसार होंगे:-

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग (रु.)	
		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
1.	सभी पोत	1.13	0.68

टिप्पणियां :

- (i) बर्थ किराये की अवधि पोत द्वारा बर्थ अभिग्रहण किए जाने से गिनती की जाएगी।
- (ii) बर्थ किराये में बर्थ पर प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रभार, जैसे बर्थ का अधिग्रहण, कूड़ा हटाना, बर्थों की सफाई, फायर वॉच आदि शामिल हैं।
- (iii) यदि पोत खराबी अथवा प्रचालक की तट आधारित सुविधाओं की अनुपलब्धता की वजह से, अथवा प्रचालक पर आरोप्य किन्हीं अन्य कारणों से निष्क्रिय रहता है तो पोत के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान प्रोद्भूत पारादीप पत्तन न्यास को देय बर्थ किराया प्रभारों के समकक्ष रियायत प्रचालक द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
- (iv) (क) बर्थ किराया पोत द्वारा नौचालन के अपने तैयार होने का सिग्नल देने के समय के 4 घंटों बाद रुक जाएगा।

- (ख) बर्थ किराया की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटों की समय सीमा में पक्षीय परिस्थितियों की चाह में जलयान का प्रतीक्षा समय, खराब मौसम, और रात्रि नेविगेशन की कमी की वजह अतिरिक्त होगी।
- (ग) पोत का मास्टर/एजेंट पक्षीय ज्वारभाटा और मौसम परिस्थितियों के अनुसार नौचालन के लिए तैयार होने का सिग्नल देगा।
- (v) दंडात्मक बर्थ किराया झूठे सिग्नल के लिए एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभारों के समकक्ष होगा।
- “झूठा सिग्नल” तब दिया जाएगा जब पोत तैयार होने का सिग्नल देता है और अनुमानन में पाइलट के लिए मांग कर सकता है जब वह इंजन तैयार न होने की वजह से अबर्थिंग के लिए तैयार नहीं हो अथवा कार्गो प्रचालन पूरा नहीं हुआ हो अथवा ऐसे अन्य कारण पोतों पर आरोप्य हों। इसमें रात्रि नेविगेशन की कमी अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों की कमी, पक्षीय ज्वारभाटा नहीं होने की वसज से नौचालन में असमर्थ हो तब तैयार होने का सिग्नल देना शामिल नहीं होगा।”

5. सामान्य टिप्पणी:

संदर्भ प्रशुल्क मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएगी परन्तु 1 जनवरी 2014 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के केवल 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।

अनुबंध - II

पारादीप पत्तन में बीओटी आधार पर लौह अयस्क निर्यातों के प्रहस्तन के लिए विकसित किए जाने वाले नए लौह अयस्क बर्थ के लिए कार्यनिष्पादन मानकों की अनुसूची

1. सकल बर्थ आउटपुट

विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए टर्मिनल (सकल बर्थ आउटपुट) की उत्पादकता के साथ पैरामीटर डील करता है। लौह अयस्क के मामले में, टर्मिनल की क्षमता (अभियंत्रण, प्रहस्तन की पद्धति) और पार्सल आकार सकल बर्थ आउटपुट निर्धारित करेगा। उच्चतर टर्मिनल क्षमता और बड़े पार्सल आकार उच्च उत्पादकता को लीड करेंगे। सकल बर्थ आउटपुट उस टर्मिनल में उस माह में जलयानों के कार्यदिवसों की संख्या द्वारा गुणा किया गया टर्मिनल पर जलयान द्वारा बिताये गए समय से विभाजित करते हुए एक माह के दौरान जलयान को प्रहस्तित कुल कार्गो परिकलित किया जाएगा। जलयान घंटों से कार्य दिवसों की संख्या का निर्धारण करते समय, 4 घंटों का बर्थ भत्ता कुल घंटों से घटाया जाएगा।

लौह अयस्क के लिए सकल बर्थ आउटपुट के लिए प्रतिमान 60,000 टन/दिन होगा। निर्धारित कार्यनिष्पादन मानक पूरा करने में कमी के मामले में भारतोलन 70 प्रतिशत होगा।

2. स्थानांतरण भंडारण विराम समय:

बल्क कार्गो:

लौह अयस्क के लिए अंतरण भंडारण विराम समय की गणना की जाएगी, क्योंकि निम्नलिखित कार्यपद्धति के अनुसार पत्तन प्रतिदिन से कार्गो के औसत निपटान द्वारा विभाजित एक माह में उपर्युक्त कार्गो पोतों के औसत पार्सल आकार के आधा रूप में:

कार्गो प्रतिदिन का औसत निपटान (क) = (ओबी+प्राप्त/प्रेषित-सीबी)/ दिनों की सं.

ओबी = ओपनिंग बैलेंस, सीबी = क्लोजिंग बैलेंस

औसत पार्सल आकार (ख) = (पी1 + पी2++पीएन)/ एन (पार्सलों की सं.)

पी1, पी2 पीएन एक माह में प्रत्येक पोत के पार्सल आकार हैं।

बल्क कार्गो के लिए स्थानांतरण भंडारण समय = 0.5 (ख/क)

लौह अयस्क के लिए स्थानांतरण विराम समय लदाई प्रचालन की शुरुआत तक 18 दिन होगा।

निर्धारित कार्यनिष्पादन मानक पूरा करने में कमी के मामले में भार 20 प्रतिशत है।

3. प्राप्ति/डिलीवरी प्रचालन के लिए घुमाव समय:

प्राप्ति/डिलीवरी प्रचालन के लिए घुमाव समय एक माह में तैनात किए गए रैकों की संख्या द्वारा विभाजित कार्गो की उतराई के लिए लिया गया समय, जैसी स्थिति हो, का जोड़ होगा। इसके अलावा, यदि टर्मिनल में एक प्रविष्टि पर उतराई और लदाई दोनों प्रचालन करते हैं, आबंटित समय उन रैकों का दोगुना होगा।

प्रतिमान निम्नलिखित होंगे:-

- लौह अयस्क के लिए रैक (एकल प्रचालन) : 10 घंटे
- लौह अयस्क के लिए रैक (दोगुना प्रचालन) : 18 घंटे

58 बॉक्सएन वैगन प्रति रैक

निर्धारित कार्यनिष्पादन मानक पूरा करने में कमी के मामले में भार 10 प्रतिशत है।

लिविडेटेड नुकसानों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और गणना:

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रियायतप्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषित रिपोर्टों और/अथवा रियायतप्राप्तकर्ता के रिकॉर्डों और/अथवा रियायतप्रदाता प्राधिकरण द्वारा प्रेषित रिपोर्टों की तिमाही समीक्षा की जाएगी। रियायतप्राप्तकर्ता को औसत कार्यनिष्पादन में 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की प्रत्येक कमी के लिए तत्संबंधी तिमाही के सकल राजस्व के 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर पर निर्धारित लिविडेटेड नुकसानों की अदायगी करनी होगी जोकि निम्नलिखित तरीके से मूल्यांकित किया जाएगा।

प्रत्येक कार्यनिष्पादन मानक नीचे दर्शाए गए तरीके से औसत रूप में परिकलित किया गया है।

मानक के सापेक्ष वास्तविक औसत कार्यनिष्पादन निर्धारित मानक के प्रति मूल्यांकित किया जाएगा। यह कमी निर्धारित मानक के प्रतिशत रूप में परिकलित की जाएगी। प्रत्येक कार्यनिष्पादन मानक के मामले में कमी इसे सौंपा गया भार होगा। औसत कार्यनिष्पादन में समग्र कमी प्रत्येक कार्यनिष्पादन मानक के मामले में भारित कमियों के जोड़ रूप में निर्धारित की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि $x\%$ द्वारा सकल बर्थ आउटपुट में कमी की जाती है, $y\%$ द्वारा स्थानांतरण भंडारण विराम समय और $z\%$ द्वारा प्राप्ति/डिलीवरी प्रचालनों के लिए घुमाव समय और ऐसी कमियों को सौंपे गए भार क्रमशः 0.7, 0.2 और 0.1 है, तब औसत कार्यनिष्पादन में समग्र कमी $(0.7x+0.2y+0.1z)\%$ होगी।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th June, 2014

No. TAMP/28/2014-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for re-fixation of Reference tariff for a new iron ore berth to be developed for handling of iron ore exports at Paradip Port on BOT basis, under the Guidelines for Determination of Tariff for Port Projects at Major Ports, 2013, which were notified vide Notification No. TAMP/18/2013-Misc. dated 30 September 2013 vide Gazette No. 254, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

(No. TAMP/28/2014-PPT)

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri C. B. Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 5th day of June, 2014)

This case relates to the proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for re-fixation of Reference tariff for a new iron ore berth to be developed for handling of iron ore exports at Paradip Port on BOT basis, under the Guidelines for Determination of Tariff for Port Projects at Major Ports, 2013.

1.2. This Authority has passed an order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 fixing upfront tariff for a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth to be developed at the Paradip Port Trust (PPT), in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports, 2008. This Order was notified in the Gazette of India on 16 August 2008 vide Gazette no. 133.

2.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PR-14019/16/2012-PG dated 31 July 2013 has issued 'Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013' under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 on 31 July 2013. In compliance of the policy directives issued by the (MOS) under Section 111 of the MPT Act, 1963, the said Guidelines were notified vide Notification No. TAMP/18/2013-Misc. in the Gazette of India on 8 August 2013, vide Gazette no. 214. The said Guidelines have come into effect from 31 July 2013.

2.2. Subsequently, the MOS issued revised Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts Act and made it effective from 9 September 2013. The said revised guidelines were notified in the Gazette of India on 30 September 2013 vide Gazette No. 254.

3.1. In pursuance of the Guidelines for Determination of Tariff for Port Projects at Major Ports, 2013 and based on a proposal filed by the PPT in August 2013, this Authority vide its Order no. TAMP/37/2013-PPT dated 30 August 2013 has fixed Reference tariff for a Deep Draught Iron Ore berth of

10 MMTPA Capacity to be developed on BOT basis at PPT. This Order has been notified in the Gazette of India on 20 September, 2013 vide Gazette No. 245.

3.2. It is noteworthy that the Reference tariff so fixed in August 2013 was based on the upfront tariff rates of iron ore project at PPT approved in the year 2008 (as mentioned in the initial para above) after applying the due escalation factor.

3.3. Subsequently, this Authority has passed an Addendum dated 5 December, 2013 to the Order dated 30 August 2013, to prescribe some relevant clauses as stipulated in the Guidelines of 2013, in the PPT Order also. The Addendum was notified in the Gazette of India on 26 December 2013 vide Gazette no. 333.

4. In this backdrop, the PPT under cover of its letter dated 16 May, 2014 has filed a proposal for re-fixation of Reference tariff for a new iron ore berth to be developed for handling of iron ore exports at Paradip Port on BOT basis, under the Guidelines for Determination of Tariff for Port Projects at Major Ports, 2013. The main points made by the PPT in its proposal are given below:

- (i) The notification for upfront tariff for the 'Deep draught Iron Ore berth on BOT basis at Paradip Port' was issued on 16 August, 2008.
- (ii) These tariff were indexed vide case No. TAMP/37/2013-PPT dated 30 August 2013 and the project was put to retender.
- (iii) However, it has now been decided to discharge the present tender and re-invite bids from the RFQ stage. RFQ for the same will be issued in May 2014. As RFP documents for the project should contain proposed tariff for the project indexed to 2014 for various services, the Tariff Proposal has been prepared based on "Revised Guidelines for determination of Tariff for projects at Major Ports, 2013 notified on 30 September 2013.
- (iv) The tariffs have been indexed by 31.58% based on approved tariff of 2008 (i.e. 4.3% based of approved tariff of 2013).

4.2. The PPT has furnished the 'Reference Tariff Schedule for Iron Ore Terminal and the Performance Standards along with its proposal.

5. With reference to the totality of the information collected, the following points emerge for consideration:

- (i) Based on the upfront tariff fixed for an iron ore berth at PPT in July 2008, this Authority vide its Order of August 2013 has fixed Reference tariff for the iron ore facility at the PPT. The Reference tariff so fixed was after applying an escalation factor of 26.15% (being the applicable indexation factor for the year 2013 to be applied for tariff with base WPI as on 1 January, 2008).
- (ii) On the ground that the PPT has decided to discharge its tender and re-invite bids and that since the RFP documents for the project should contain proposed tariff for the project indexed to 2014 for various services, the PPT has submitted the proposal in reference.
- (iii) Clause 2.8 of the 2013 Guidelines stipulates that Bids for award of PPP projects will be invited and evaluated on the basis of Reference Tariff prevalent at that time. Since the PPT proposes to invite bids during the year 2014, there appears to be a need to prescribe Reference tariff as applicable for the year 2014.
- (iv) The Revised Guidelines of 2013 stipulate that while adopting the Reference tariff, the tariff set under the Tariff Guidelines of 2008 shall be escalated to the extent of 60% of WPI per annum, as provided in the said guidelines for the period between 1st January of the year as prescribed in the relevant tariff order of this Authority under 2008 guidelines and 1st January of the subsequent relevant year when the Reference Tariff for the particular project in question is being notified.
- (v) As stated earlier, the upfront tariff for the PPT iron ore berth was notified in July 2008. The Upfront Tariff Schedule of PPT specifically states that the base year of Wholesale Price Index (WPI) for indexation in the reference tariff rates approved in the said Order will be 1 January 2008. Accordingly, the PPT has applied the indexation factor of 31.58% on the tariff caps approved for the PPT iron ore berth vide Order of July 2008. This

indexation factor is seen to be the indexation factor communicated by us to all the Major Port Trusts to be applicable for reference tariff fixed in the year 2014 with base WPI as on 1 January 2008. The indexed reference tariff for the iron ore berth as derived by the PPT based on the indexation factor of 31.58%, as applicable for the year 2014, is found to be in order.

- (vi) In the proposed reference tariff schedule, the PPT has not proposed the definitions and the general terms and conditions forming part of the PPT Reference tariff Schedule. Further, the various conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges are also not seen to have been proposed by the PPT. In this regard, it is relevant here to mention that the upfront tariff schedule for the iron ore berth at PPT approved in July 2008 did not prescribe the definitions, general terms and conditions and the various conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges, which is generally prescribed in the Upfront tariff Schedule of the various major port trusts. Therefore, definitions, general terms and conditions and all other conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges forming part of the Upfront tariff Schedule for iron ore handling at the Mormugao Port Trust (MOPT) (Order No. TAMP/60/2009-MOPT dated 4 May 2010) are suitably prescribed in the Reference tariff Schedule of PPT also.
- (vii) Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2013 requires this Authority to prescribe the Reference Tariff along with the Performance Standards. The performance standards and the conditionalities governing the performance standards proposed by PPT are found to be similar to those notified by this Authority vide Order dated 30 August 2013. Therefore, the performance standards and the conditionalities as proposed now by PPT is notified without any modification.
- (viii) The note proposed by PPT governing the indexation of reference tariff for future period is with reference to 1 January, 2013. Since the reference tariff is fixed in the year 2014 duly updated as of 31 December, 2013, as proposed by PPT, indexation for future period will be with reference to 1 January, 2014. Therefore, the following General note is prescribed in the Reference tariff Schedule of PPT for automatic adjustment in tariff caps for every subsequent years:

“The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2014 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31st March of the following year.”

6.1. Subject to above, the Reference Tariff Schedule proposed by the Port has been modified. The modified Reference Tariff Schedule is attached as **Annex – I** and the Performance Standards for the Iron ore Berth as proposed by the port, is attached as **Annex – II**.

6.2. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, the modified Reference Tariff Schedule for the Iron ore Berth at PPT is approved and notified along with the Performance Standards.

6.3. As per clause 2.5 of the Revised Tariff Guidelines 2013, the Reference Tariff and Performance Standards notified by this Authority shall be mentioned in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects. Accordingly, the PPT is advised to incorporate the Reference Tariff and Performance Standards, in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects.

7.1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.

However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the “Performance Linked Tariff”) from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial

year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

7.2. The proposal shall be submitted to this Authority along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation, as the case may be.

7.3. On receipt of the proposal, this Authority will seek the views of the PPT on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.

7.4. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, this Authority will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Operator shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

7.5. After considering the views of the PPT, if this Authority is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.

7.6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, this Authority will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. This Authority will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the operator. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.

7.7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the PPP operator shall be automatically notified by this Authority subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The PPP operator, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and this Authority shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

7.8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by this Authority, he may prefer a representation to this Authority which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding PPT. The PPT will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.

7.9. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to this Authority which will host it on its website.

7.10. The PPP operator shall furnish to this Authority quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operator within a month following the end of each quarter. Any other information which is required by this Authority shall also be furnished to them from time to time.

7.11. This Authority shall publish on its website all such information received from PPP operator. However, this Authority shall consider a request from any PPP operator about not publishing certain data/ information furnished which is commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/ information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation of upon publication. The decision of this Authority in this regard would be final.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Annex – I

Reference Tariff Schedule for the New Iron Ore berth to be developed for handling Iron Ore exports at Paradip Port on BOT Basis.**1.1 DEFINITIONS:**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definition shall apply.

- (i). “Coastal Vessel” means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
- (ii). “Foreign Vessel” means any vessel other than a coastal vessel.
- (iii). “Per Day” means per calendar day unless otherwise stated.

1.2 GENERAL TERMS AND CONDITIONS:

- (i). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is ‘coastal’ or ‘foreign-going’ for the purpose of levy of vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii). (a). The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.
- (b). The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
- (c). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from / to quay to/ from storage yard including wharfage.
- (d). Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port ‘A’ for subsequent transshipment to Indian Port ‘B’ will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (iii). Interest on delayed payments/refunds.
 - (a). The User shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b). The rate of penal interest will be 2% above the Prime Lending Rate of the State Bank of India.
 - (c). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the Users, whichever is later.
 - (d). The delay in payment by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Terminal Operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (iv). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (v). (a). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels, likewise, rebates and discounts are floor levels. The operator may, if they so desire, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.
- (b). The operator may also, if they so desire rationalize the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the users in the rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.

- (c). The operator should notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further charges in such lower rates and/or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rate notified by the TAMP.

- (vi). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the operator.

2. CARGO HANDLING CHARGES:

The cargo handling charges at the New Iron Ore berth for handling Iron Ore Exports at Paradip Port Trust shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:

Sl. No.	Commodity	Unit	Rate in ₹
1.	Iron Ore handling charges (all types)	MT	206.58

Note : The above rate is the composite rate for unloading the Iron Ore from the railway wagon, conveying to stack yard, storage at the stack yard upto free period of 18 days after the time of unloading the iron ore from railway wagon, reclaiming from stack yard and loading on to the ship and all other miscellaneous services provided.

3. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(₹ per MT per day)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6th day to 10th day for the balance cargo	Rate for 11th onwards for the balance cargo
1.	Iron Ore (all types)	15.79	31.58	63.16

Notes :

- For the purpose of calculation of free period Customs notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- Free period for import cargo shall be reckoned from the day following the day of completion of final discharge from the vessel.
- Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.

4. BERTH HIRE CHARGES:

The Berth Hire charges payable by masters/owners/agents for the vessel shall be as per rates below:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof (₹)	
		Foreign Going Vessel	Coastal Vessel
1.	All Vessels	1.13	0.68

Notes:

- The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupies the berth.
- Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch, etc.
- In case vessel idles due to breakdown or non availability of the shore based facilities of the operator, or any other reasons attributable to operator, rebate equivalent to berth hire charges payable to the Paradip Port Trust accrued during the period of idling of vessel shall be allowed by the operator.
- (iv). (a). Berth hire shall stop 4 hours after the time of vessel signaling its readiness to sail.

- (b). The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather, and due to lack of night navigation.
- (c). The master / agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.
- (v). The Penal Berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charge for a false signal.
 "False signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes the signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions."

5. GENERAL NOTE:

The Reference Tariffs will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2014 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of Reference Tariffs will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

Annex - II

Schedule of Performance Standards for the New Iron Ore berth to be developed for handling Iron Ore exports at Paradip Port on BOT Basis.

1. Gross Berth Output

The parameter deals with the productivity of the terminal (Gross Berth Output) for different types of cargo. In case of iron ore, the capability of the terminal (mechanization, method of handling) and parcel size will determine the Gross Berth Output. Higher terminal capability and greater parcel size will lead to high productivity. The Gross Berth Output shall be calculated as the total cargo handled to the ship during a month divided by the time spent by the ship at the terminal multiplied by number of working days of ships in that month at that terminal. While determining the number of working days from the ship hours, the berth allowance of 4 hours shall be subtracted from the total hours.

The norm for Gross Berth Output for Iron Ore will be 60,000 Tons/day. Weightage in case of shortfall in meeting the prescribed performance standard will be 70%.

2. Transit Storage Dwell Time:

Bulk Cargo:

The Transit Storage Dwell Time for iron ore shall be calculated, as half of average parcel size of above cargo vessels in a month divided by average disposal of cargo from the port per day as per the following methodology:

Average disposal of Cargo per day (A) = (OB+Received/Despatched-CB)/No. of days

OB = Opening Balance, CB = Closing Balance.

Average Parcel Sizes (B) = (P1 + P2++Pn)/n (no. of parcels)

P1, P2 Pn are parcel size of each vessel in a month.

Transit storage Time for Bulk Cargo = 0.5 (B/A)

The transit dwell time for iron ore will be 18 days up to commencement of ship loading operation.

Weightage in case of a shortfall in meeting the prescribed performance standard is 20%.

3. Turnaround Time for receipt/delivery operation:

The Turnaround Time for receipt/delivery operation shall be the sum of time taken for unloading of cargo divided by the number of rakes deployed, as the case may be, in a month. Further, in case the

rake does both unloading and loading operations on a single entry into the terminal, the time allocated shall be doubled for those rakes.

The norms will be as follows:

- Rake for Iron Ore (Single operation) : 10 hours
- Rake for Iron Ore (Double operation) : 18 hours

58 BOXN wagons per rake

Weightage in case of a shortfall in meeting the prescribed performance standard is 10%.

Performance Evaluation and calculation of liquidated damages:

Performance evaluation shall be made on a quarterly review of the reports furnished by the concessionaire and/or the records of the Concessionaire and/or by an enquiry by the Concessioneing Authority. The Concessionaire shall be liable to pay liquidated damages determined at the rate of 1% (one per cent) of the Gross Revenue of the respective quarter for every shortfall of 10% (ten per cent) in the average performance which shall be assessed in the following manner.

Each Performance Standard is calculated as an average in the manner indicated above.

The actual average performance vis-à-vis a standard will be evaluated against the prescribed standard. The shortfall will be computed as a percentage of the prescribed standard. The shortfall in respect of each performance standard will have a weightage assigned to it. The overall shortfall in average performance shall be assessed as the aggregate of the weighted shortfalls in respect of each of the performance standards. For example, if there is a shortfall in Gross Berth Output by x%, Transit Storage Dwell Time by y% and Turn round time for receipt/delivery operations by z% and the weightage assigned to such shortfalls is 0.7, 0.2 and 0.1 respectively, then the overall shortfall in average performance will be $(0.7x+0.2y+0.1z)\%$.